बृहस्पतिवार
34 साल से देहरादून का विश्वास
30 जुलाई 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 187
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

केदारनाथ पैदल मार्ग बंद!

गौरीकुंड के आगे पहाड़ी से भारी भूस्खलन

हमारे संवाददाता

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक बार फिर भूस्खलन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गौरीकुंड गेट से करीब 200 मीटर आगे भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से पैदल मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल यात्रियों की आवाजाही रोक दी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ही क्षणों में पहाड़ी से तेज गर्जना के साथ भारी मलबा और पत्थर नीचे आने लगे। यदि उस समय श्रद्धालु मार्ग पर होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई।

भूस्खलन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, डीडीआरएफ और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मार्ग से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और ऊपर से गिरते पत्थरों के कारण राहत एवं बहाली कार्य में भारी दिक्कतें आ रही हैं। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड गेट से लगभग 200 मीटर आगे पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। प्रशासन ने तत्काल यात्रियों की आवाजाही रोकते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यात्रा मार्ग बाधित होने की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों, राहत एवं बचाव दलों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। मार्ग से मलबा हटाने एवं आवागमन बहाल करने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। हालांकि, क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा और पहाड़ी से रुक-रुक कर मलबा एवं पत्थर गिरने के कारण राहत एवं मार्ग बहाली कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं एवं यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, बिना अनुमति के आगे बढ़ने का प्रयास न करें तथा जिला प्रशासन, पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन करें। यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही श्रद्धालुओं की आवाजाही पुन: सुचारु रूप से प्रारंभ कराई जाएगी।

प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, बिना अनुमति आगे बढ़ने का प्रयास न करें तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। फिलहाल केदारनाथ पैदल यात्रा पूरी तरह स्थगित है। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासन के अगले आदेश का इंतजार करने की अपील की गई है।

दूसरी ओर चमोली में देर रात से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई संपर्क मार्गों पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से बिना आवश्यक कारण यात्रा न करने की अपील की है। बताया गया कि देर रात से जारी बारिश के कारण बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागलनाला, भनेर पानी और नंदप्रयाग सहित कई स्थानों पर मलबा आने से बाधित हो गया। हालांकि नंदप्रयाग के पास मार्ग को प्रशासन ने सुचारु कर दिया है। वहीं नंदप्रयाग-नंदानगर मोटर मार्ग मंगरौली के पास मलबा आने से बंद हो गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली करीब दो दर्जन सड़कें भी अवरुद्ध हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बद्रीनाथ धाम में भगवान का मुकुट चुराने वाला गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

चमोली। बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण का मुकुट चुराने वाले एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से 5 लाख रूपये का सोने का मणि जड़ित मुकुट व नगदी बरामद की गयी है।

जानकारी के अनुसार बीती 27 जुलाई को ब्रह्मचारी भगवत दास, ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम, ब्रह्मकपाल द्वारा थाना कोतवाली श्री बद्रीनाथ में तहरीर देकर बताया गया था कि आश्रम में भजन-कीर्तन हेतु शरण लेने वाले साधु राघवदास ने दिनांक 24 जुलाई 2026 की रात्रि मंदिर से भगवान नारायण का लगभग 5 लाख रूपये मूल्य का सोने का मणि जड़ित मुकुट एवं नकदी चोरी कर ली है। मामले

❑5 लाख मूल्य का सोने का मणि जड़ित है बरामद मुकुट

में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल एवं उसके आसपास गहन छानबीन की। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए आरोपी की तलाश निरंतर जारी रखी गयी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम द्वारा बीती शाम एक सूचना के आधार पर बद्रीश गंगा वाटिका गेट (हनुमानचट्टी रोड) के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे आरोपी राघवराम पाठक उर्फ राघवदास पुत्र श्यामता प्रसाद पाठक, निवासी ग्राम मुनीमपुर, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) को पुलिस टीम ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जिसकी निशानदेही पर भगवान नारायण का चोरी गया सोने का मणि जड़ित मुकुट व चोरी की गई नकदी में से 4,500 रूपये तथा घटना में प्रयुक्त काला बैग बरामद कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने आश्रम के मंदिर से भगवान नारायण का सोने का मुकुट तथा वहीं ठहरे प्रभुदास नामक व्यक्ति के बैग से नकदी चोरी की थी। बहरहाल पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

दून वैली मेल

संपादकीय

पेपर लीक माफिया पर स्ट्राइक

देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया के खिलाफ आखिरकार संसद ने सख्त संदेश देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पारित होना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों के संघर्ष और आक्रोश की प्रतिध्वनि है, जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन कुछ संगठित गिरोहों और भ्रष्ट तंत्र की वजह से उनका भविष्य दांव पर लग गया। पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता हो जब किसी न किसी भर्ती परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर सामने न आई हो। कभी पुलिस भर्ती, कभी शिक्षक भर्ती, कभी पटवारी, कभी मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं, तो कभी अन्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाएंकृलगातार सामने आए मामलों ने युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली से हिला दिया। लाखों अभ्यर्थियों की वर्षों की तैयारी कुछ घंटों में बेकार हो जाती थी, जबकि असली लाभ संगठित अपराध के उन नेटवर्कों को मिलता था, जिन्होंने शिक्षा और रोजगार को कमाई का धंध ा बना दिया। यही कारण है कि एंटी पेपर लीक कानून को लंबे समय से जरूरी माना जा रहा था। सरकार का दावा है कि नया कानून पेपर लीक कराने वालों, प्रश्नपत्र खरीदने-बेचने वाले गिरोहों, तकनीकी माध्यमों से परीक्षा में धांधली करने वालों और ऐसे अपराध में शामिल संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यदि कानून का क्रियान्वयन प्रभावी हुआ, तो यह परीक्षा माफिया के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन केवल कठोर सजा किसी समस्या का स्थायी समाध ान नहीं होती। देश में पहले भी कई कानून बने, पर अपराध पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। सवाल यह है कि क्या परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही भी उतनी ही सख्त होगी? यदि प्रश्नपत्र सुरक्षित रखने, डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और परीक्षा केंद्रों की निगरानी में लापरवाही होती है, तो केवल अपराधियों को दंडित करने से व्यवस्था में भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं होगा। असल समस्या कानून से पहले व्यवस्था की है। पेपर लीक की अधिकांश घटनाओं में सामने आया कि कहीं न कहीं सिस्टम के भीतर से जानकारी बाहर गई, सुरक्षा में सेंध लगी या कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत रही। यदि प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं होगी, तो नए कानून का प्रभाव सीमित रह सकता है। इस कानून के साथ सरकार को परीक्षा सुधार का व्यापक एजेंडा भी लागू करना चाहिए। आधुनिक एन्क्रिप्शन, सुरक्षित डिजिटल प्रश्नपत्र वितरण, बायोमेट्रिक सत्यापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, परीक्षा केंद्रों का स्वतंत्र आडिट और समयबद्ध जांच जैसी व्यवस्थाएं अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी हैं। जितनी तेजी से अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से परीक्षा प्रणाली को आध ुनिक बनाना होगा। इस पूरे मुद्दे का सबसे संवेदनशील पक्ष युवाओं का विश्वास है। पेपर लीक केवल एक परीक्षा रद्द नहीं करता, बल्कि लाखों युवाओं के मन में यह सवाल पैदा करता है कि क्या मेहनत का कोई मूल्य बचा है? जब बार-बार परीक्षाएं निरस्त होती हैं, भर्ती वर्षों तक लटकती है और दोषियों पर कार्रवाई में देरी होती है, तब निराशा बढ़ती है। यही निराशा कई बार सामाजिक असंतोष और व्यापक विरोध प्रदर्शनों का कारण भी बनती है। विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे राज्यों का अनुभव बताता है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने युवाओं के भीतर गहरा अविश्वास पैदा किया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और कई गिरफ्तारियां भी हुईं। इससे यह स्पष्ट है कि समस्या केवल कानून की कमी नहीं थी, बल्कि व्यवस्था की कमजोरियों की भी थी। इसलिए अब देश की नजर इस बात पर होगी कि नया कानून जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है। राजनीतिक दलों को भी इस विषय पर आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठना होगा। पेपर लीक किसी एक सरकार या एक राज्य की समस्या नहीं है। यह राष्ट्रीय स्तर की चुनौती है। यदि संसद इस मुद्दे पर एकमत होकर युवाओं के हित में मजबूत कानून बनाती है, तो यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। लेकिन कानून बनने के बाद उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी पालना ही उसकी असली परीक्षा होगी। युवाओं की सबसे बड़ी अपेक्षा केवल कठोर सजा नहीं, बल्कि निष्पक्ष अवसर है। उन्हें यह भरोसा चाहिए कि परीक्षा में उनकी सफलता का आधार केवल उनकी मेहनत होगी, न कि किसी गिरोह की पहुंच या पैसे का प्रभाव। यही किसी भी लोकतांत्रिक और मेरिट आधारित व्यवस्था की पहचान है। लोकसभा ने कानून पारित कर अपना दायित्व निभा दिया है। अब बारी सरकार, परीक्षा एजेंसियों, जांच संस्थाओं और राज्यों की है कि वे यह साबित करें कि भारत में प्रतिभा बिकाऊ नहीं है और युवाओं के सपनों की कीमत किसी पेपर लीक माफिया से कम नहीं। जिस दिन एक भी अभ्यर्थी को यह विश्वास हो जाएगा कि उसकी मेहनत सुरक्षित है, उसी दिन इस कानून की वास्तविक सफलता मानी जाएगी।

सोशल मीडिया 'ट्रेंड' और चुनावी 'दावे'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर रोज नए दावे सामने आ रहे हैं कहीं भाजपा की वापसी तय बताई जा रही है, कहीं कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी हो रही है, तो कहीं क्षेत्रीय दलों को किंगमेकर बताया जा रहा है। लेकिन जब इन दावों की पड़ताल की जाती है, तो तस्वीर कहीं अधिक जटिल दिखाई देती है। क्या भाजपा पूरी तरह मजबूत स्थिति में है?भाजपा लगातार तीसरी बार आसानी से सरकार बना लेगी। यह दावा अभी प्रमाणित नहीं कहा जा सकता।

भाजपा के पास मजबूत संगठन, बूथ स्तर का नेटवर्क और सत्ता का लाभ है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को चुनावी अभियान का आधार बनाया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, रेल और हवाई संपर्क, निवेश, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, स्थानीय भर्ती, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चुनौतियां विपक्ष को मुद्दे भी दे रही हैं। इसलिए भाजपा की राह पूरी तरह आसान कहना जल्दबाजी होगी।

यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी के करीब है और जनता पूरी तरह सत्ता परिवर्तन चाहती है। इसका भी अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, पलायन और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यदि पार्टी संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखती है और बूथ स्तर तक मजबूत अभियान चलाती है, तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को पूरी तरह सक्रिय रखना और मतदाताओं के सामने स्पष्ट वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है।

◆सचमुच बन रही है सत्ता की तस्वीर, या अभी केवल राजनीतिक शोर
◆दावों, चर्चाओं व सोशल मीडिया के बीच यह है चुनाव की हकीकत
◆सोशल मीडिया पर दावों से अलग है उत्तराखंड में जमीनी हकीकत

केवल सत्ता विरोधी माहौल की उम्मीद चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होती।

इसके साथ ही यह भी अभी से दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय दल इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और इस बार क्षेत्रीय दल सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह सीट-दर-सीट प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार कुछ क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। यदि मुकाबला बेहद करीबी हुआ और किसी बड़े दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो छोटे दलों की भूमिका बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल यह कहना कि वे निश्चित रूप से किंगमेकर बनेंगे, तथ्यों से परे होगा।

इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक और बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेंगे और यह एक मजबूत संभावना है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, रोजगार, युवाओं का भविष्य और सरकारी नौकरियों का मुद्दा चुनावी बहस में प्रमुख स्थान पा सकता है। हालांकि चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं लड़े जाते। विकास, सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, महिला कल्याण, किसान और स्थानीय पहचान जैसे मुद्दे भी समान रूप से प्रभाव डाल सकते हैं।

सोशल मीडिया ही चुनाव का परिणाम तय करेगा यह तो संभव नहीं है। सोशल मीडिया माहौल बना सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जिताता। उत्तराखंड में अब भी बूथ प्रबंधन, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्रीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वायरल वीडियो और ट्रेंडिंग हैशटैग हमेशा मतपेटी में वोट में नहीं बदलते। भाजपा विकास कार्यों, डबल इंजन सरकार, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, निवेश और केंद्र-राज्य समन्वय को अपने अभियान का आधार बनाएगी। संगठनात्मक मजबूती उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। कांग्रेस रोजगार, महंगाई, पलायन, भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, किसानों और स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। उसका प्रयास सत्ता विरोधी भावना को राजनीतिक समर्थन में बदलने का होगा। यूकेडी स्थानीय अस्मिता और पहाड़ के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा। आम आदमी पार्टी शिक्षा

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

'विधानसभा' फतह के लिए की 'किलाबंदी'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। लोकसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस ने अपनी पूरी राजनीतिक ऊर्जा आगामी विधानसभा चुनावों पर केंद्रित कर दी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी ने देशभर में अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट है जनता के बीच यह संदेश पहुंचाना कि वह भाजपा के विकल्प के रूप में खुद को फिर से स्थापित करना चाहती है। पार्टी का चुनाव अभियान केवल रैलियों तक सीमित नहीं है। गांव-गांव जनसंपर्क, सोशल मीडिया पर आक्रामक उपस्थिति, बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और युवाओं, महिलाओं तथा किसानों के बीच अलग-अलग अभियान चलाने की रणनीति पर काम हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि चुनाव केवल बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि बूथ स्तर के संगठन और स्थानीय मुद्दों से जीते जाते हैं।

उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस विशेष रूप से महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का दावा है कि युवाओं में रोजगार और पारदर्शी भर्ती को लेकर असंतोष है, जिसे वह अपने अभियान का केंद्र बनाएगी। कांग्रेस की रणनीति का दूसरा बड़ा आधार स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। पिछले चुनावों में यह आरोप लगता रहा कि पार्टी का अभियान केंद्रीय नेतृत्व पर अधिक निर्भर रहा। इस बार कोशिश है कि राज्य स्तर के नेताओं को अधिक जिम्मेदारी मिले और स्थानीय समस्याओं को स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भों में जनता तक पहुंचाया जाए।

◆चुनावी मोड में कांग्रेस, सत्ता की राह तलाशने निकल गई है कांग्रेस पार्टी
◆महंगाई, बेरोजगारी और जनमुद्दों को हथियार बना आक्रामक मोड में पार्टी
◆सिर्फ रैलियों से नहीं, जमीनी किलाबंदी से भाजपा को घेरने का बना प्लान

हालांकि कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने की है। कई राज्यों में गुटबाजी, संसाधनों की कमी और बूथ स्तर पर कमजोर नेटवर्क अभी भी पार्टी के सामने बड़ी बाधा हैं। भाजपा जहां अपने मजबूत संगठन और व्यापक चुनावी मशीनरी के साथ मैदान में उतरती है, वहीं कांग्रेस को हर सीट पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का चुनाव अभियान तभी प्रभावी होगा जब वह केवल सरकार की आलोचना तक सीमित न रहे, बल्कि शासन, रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टि भी प्रस्तुत करे। मतदाता अब केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ठोस समाधान भी सुनना चाहता है। भाजपा भी कांग्रेस के अभियान का जवाब अपने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर देने की तैयारी में है। ऐसे में आगामी चुनावों में मुकाबला केवल नारों का नहीं, बल्कि संगठन, नेतृत्व और जनविश्वास का होगा।

आने वाले महीनों में कांग्रेस का चुनाव अभियान और अधिक आक्रामक होने की संभावना है। यदि पार्टी स्थानीय मुद्दों, मजबूत संगठन और स्पष्ट वैकल्पिक एजेंडे के साथ जनता के बीच लगातार बनी रहती है, तो कई राज्यों में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वहीं यदि आंतरिक मतभेद और संगठनात्मक कमजोरियां हावी रहीं, तो चुनावी चुनौती और कठिन हो जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी रणभेरी बज चुकी है। भाजपा अपनी उपलब्धियों के साथ मैदान में है, जबकि कांग्रेस जनता के मुद्दों को हथियार बनाकर सत्ता की राह तलाश रही है। अब फैसला अंततः मतदाता के हाथ में होगा कि वह किसकी राजनीति और किसके विजन पर भरोसा करता है।

मेडिकल कॉलेज की जगह बदलने पर भड़के लोग, 16 अगस्त से उग्र आंदोलन की चेतावनी

नई टिहरी(आरएनएस)। टिहरी मेडिकल कॉलेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने इणिया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को नरेंद्रनगर के फिपल्टी में बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में सांकेतिक प्रदर्शन कर मांग के समर्थन में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पूर्व निर्धारित स्थान पर इणिया में ही मेडिकल कॉलेज निर्माण करने की मांग की है। ऐसा न होने पर 16 अगस्त से चरणबद्ध उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी।

टिहरी मेडिकल कालेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले व्यापार मंडल नई टिहरी, बौराड़ी सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने कलेक्ट्रेट में सांकेतिक प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज को नरेंद्रनगर के फिपल्टी ले जाने के विरोध में नारेबाजी कर आक्रोश जताया। संघर्ष समिति संयोजक डॉ. राकेश भूषण गोदियाल ने कहा कि 25 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने टिहरी भ्रमण के दौरान नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी।

इससे पूर्व तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा भी नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनने की घोषणा कर चुके हैं। वर्ष 2022 तथा 23 में मेडिकल कॉलेज के लिए भागीरथीपुरम के समीप इणिया में जगह चयनित की गई। उक्त स्थान टीएचडीसी ने भूमि जांच आदि प्रक्रिया शुरू करवा दी थी। लेकिन बीते 25 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेडिकल कॉलेज को गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के गजा तहसील के फिपल्टी में कराए जाने की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजी गई। जिससे टिहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

कहा कि दो-दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सभी प्रक्रियाओं को दर किनार करते हुए फिपल्टी में मेडिकल कॉलेज की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजी। मेडिकल कॉलेज को अन्यत्र लेने के विरोध के विरोध में 31 जुलाई को नई टिहरी में प्रदर्शन किया जाएगा। 16 अगस्त से आंदोलन को चरणबद्ध ढंग आंदोलन चलाया।

इस मौके पर समिति के सह संयोजक भगवान सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, सुंदरलाल उनियाल, कमल सिंह महर, जगजीत नेगी, जीतराम भट्ट, नरोत्तम जखमोला, कुलदीप पंवार, शिवराज सजवाण, संदीप रावत, विद्या नेगी, अनीता कंडियाल, गंगा भगत नेगी, देवेंद्र नौडियाल, अनुराग पंत, एमएल सेमल्टी, सीपी डबराल, मायाराम थपलियाल, टीकम चौहान, अनुसूया नौटियाल, आनंद तोपवाल, प्रकाश सेमवाल, मनोज चमोली, सीएस चौहान, विजय नेगी, लखवीर चौहान आदि मौजूद रहे।

पीएचसी धौंतरी बनेगा प्रसव केंद्र, सीएमओ ने किया निरीक्षण

उत्तरकाशी(आरएनएस)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय ने भटवाड़ी और डुंडा विकासखंड की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर, धौंतरी और श्रीकालखाल में स्वास्थ्य सेवाओं, अभिलेखों, दवा उपलब्धता, स्वच्छता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौंतरी के निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौंतरी जल्द ही प्रसव केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण संस्थागत प्रसव की सुविधा मिल सके। मंगलवार को पीएचसी मानपुर में सीएमओ ने निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अस्पताल में मौजूद चिकित्साधिकारी, नर्सिंग अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने और शासन के मानकों के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, उन्होंने पीएचसी धौंतरी का निरीक्षण के दौरान कहा कि पीएचसी धौंतरी को जल्द ही प्रसव केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं, उन्होंने अस्पताल में ओपीडी रजिस्टर, स्टॉक बुक, दवा उपलब्धता, अस्पताल परिसर की स्वच्छता और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएस पांगती, जूनियर इंजीनियर जगमोहन रावत आदि मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविय में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

पहाड़ की असली ताकत थी 'साझी संस्कृति'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। पहाड़ का जीवन केवल ऊंचे-ऊंचे पर्वतों, नदियों और देवस्थलों तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत रही है यहां की सामुदायिक संस्कृति। एक समय था जब गांव में किसी के खेत की बुवाई हो, किसी का घर बन रहा हो, छत पर पत्थर चढ़ाने हों, सिंचाई की गूल साफ करनी हो या किसी परिवार पर संकट आया हो पूरा गांव बिना बुलावे और बिना किसी पारिश्रमिक के एक साथ जुट जाता था। इसे ही पहाड़ में सामूहिक श्रम की परंपरा कहा जाता था। यह केवल काम करने का तरीका नहीं था, बल्कि सामाजिक जीवन का ऐसा सूत्र था जिसने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी गांवों को आत्मनिर्भर बनाए रखा। सामूहिक श्रम ने पहाड़ के लोगों को यह विश्वास दिया कि किसी एक का संकट पूरे गांव का संकट है और किसी एक की खुशी पूरे गांव की खुशी।

उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में इस परंपरा को स्थानीय बोलियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है। कहीं इसे परमा कहा गया, कहीं सहकार, तो कहीं पैंचा या अन्य स्थानीय नाम प्रचलित रहे। नाम भले बदलते रहे हों, लेकिन भावना एक ही थी आज मैं तुम्हारे खेत में काम करूंगा, कल तुम मेरे खेत में। धान की रोपाई के दिनों में गांव की महिलाएं कतार बनाकर खेतों में उतरती थीं। लोकगीतों की मधुर धुन के बीच रोपाई होती और पूरा वातावरण उत्सव जैसा हो जाता। पुरुष खेत तैयार करते, पानी की व्यवस्था संभालते या अन्य श्रम कार्य करते। इसी तरह गेहूं की कटाई, मंडाई, घास काटना, जंगल से लकड़ी लाना और पशुओं के लिए चारा जुटाना भी सामूहिक प्रयास का हिस्सा था।

पहाड़ में मकान निर्माण भी इसी सहयोग की मिसाल था। आज जहां एक मकान बनाने में ठेकेदार और बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, वहीं पहले पूरा गांव मिलकर पत्थर ढोता, लकड़ी लाता, मिट्टी तैयार करता और छत डालने तक का काम साथ करता था। बदले में केवल आत्मीयता, सम्मान और एक सामूहिक भोजन ही पर्याप्त माना जाता था। सामूहिक श्रम केवल आर्थिक मजबूरी नहीं था। यह सामाजिक सुरक्षा का भी आधार था। किसी परिवार में बीमारी हो, किसी के यहां विवाह हो, किसी के घर शोक का माहौल हो या प्राकृतिक आपदा आ जाए गांव के लोग बिना औपचारिक निमंत्रण के मदद के लिए पहुंच जाते थे। यही कारण था कि सीमित संसाधनों के बावजूद पहाड़ का सामाजिक ताना-बाना लंबे समय तक मजबूत बना रहा।

◆पहाड़ की सामूहिक श्रम परंपरा आज भी सिखाती हैं साथ चलने का मंत्र
◆बिना मजदूरी, बिना अनुबंध और बिना स्वार्थ के रहते थे मिलकर ग्रामीण
◆खेत जोतते, घर बनाते व संकट में एक-दूसरे का हाथ थामते थे सभी लोग
◆परंपरा भले ही कमजोर हो गई, लेकिन इसकी आत्मा है पहाड़ की पहचान

हालांकि बदलते समय के साथ इस परंपरा पर असर पड़ा है। गांवों से लगातार हो रहा पलायन, छोटे होते परिवार, नकद अर्थव्यवस्था का विस्तार और आधुनिक जीवनशैली ने सामूहिक श्रम की संस्कृति को कमजोर किया है। अब जिन कार्यों के लिए पहले पूरा गांव जुटता था, वहां मजदूर बुलाने की परंपरा बढ़ गई है। कई गांवों में खेत खाली पड़े हैं और पुराने लोकगीतों की गूंज भी कम सुनाई देती है। इसके बावजूद यह परंपरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी कई दूरस्थ गांवों में सिंचाई की नहरों की सफाई, मंदिरों के रख-रखाव, पैदल मार्गों की मरम्मत, जलस्रोतों के संरक्षण, वनाग्नि रोकने और आपदा के समय राहत कार्यों में सामूहिक श्रम की भावना जीवित दिखाई देती है। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से और युवा विभिन्न सामाजिक अभियानों में मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

आज के दौर में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पलायन जैसी चुनौतियों से जूझ रहे उत्तराखंड में सामूहिक श्रम की परंपरा फिर से प्रासंगिक हो सकती है। यदि ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से इस संस्कृति को नई ऊर्जा मिले, तो जल संरक्षण, पारंपरिक खेती, वन संरक्षण और ग्रामीण विकास के कई कार्य कम लागत में अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। पहाड़ ने हमेशा सिखाया है कि कठिन रास्तों को अकेले नहीं, बल्कि मिलकर पार किया जाता है। यही कारण है कि सामूहिक श्रम केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता भी है। जब समाज साथ खड़ा होता है, तब विकास केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि लोगों की सहभागिता से आगे बढ़ता है।

पुलिस ने ग्रामीणों को पढ़ाया महिला एवं साइबर सुरक्षा का पाठ

हमारे संवाददाता

उत्तरकाशी। जनपद में नशा उन्मूलन, महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्रीमती कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना मोरी पुलिस टीम द्वारा सुदूरवर्ती ग्राम देवरा में पुलिस चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

चौपाल के दौरान थानाध्यक्ष मोरी, दीपक रावत द्वारा ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उनके यथासंभव समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पुलिस एवं आमजन के मध्य आपसी विश्वास, सहयोग एवं सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया।

ग्रामीणों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि ओटीपी, सीवीवी नंबर, एटीएम/डेबिट कार्ड पिन, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड अथवा बैंक खाते से संबंधित किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक अथवा ऑनलाइन लेनदेन के प्रति सतर्क रहें तथा साइबर अथवा वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होने की स्थिति में बिना विलंब किए तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं ।

पुलिस टीम ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, महिला सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन सेवाओं तथा आपातकालीन परिस्थितियों में निर्भीक होकर पुलिस सहायता लेने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही युवाओं एवं अभिभावकों से नशे के विरुद्ध सामाजिक सहभागिता बढ़ाने और स्वस्थ, सुरक्षित एवं जागरूक समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गयी।

डिलीवरी के बाद जोड़ों में दर्द से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय

गर्भावस्था के बाद महिलाओं के जोड़ों और हड्डियों में काफी कमजोरी आ जाती है। कई बार गर्भावस्था में शारीरिक बदलावों की वजह से भी जोड़ों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है और प्रेगनेंसी के कई हफ्ते या महीने तक ऐसा रह सकता है।

अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद जोड़ों में दर्द या मासंपेशियों में दर्द या अर्थराइटिस की समस्या है तो जानिए कि किस तरह आप इस दर्द से छुटकारा पा सकती हैं।

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का काफी वजन बढ़ जाता है और यही डिलीवरी के बाद जोड़ों में दर्द का प्रमुख कारण है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के वजन को उठाने के लिए शरीर हर संभव प्रयास कर रहा होता है इसलिए जोड़ों पर दबाव पड़ने के कारण दर्द होना लाजिमी है।

कुछ मांओं को तेज दर्द और अर्थराइटिस के कारण डिलीवरी के बाद अर्थराइटिस हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द महसूस होता है। अगर आपको पहले जोड़ों में कोई चोट लगी थी तो इसकी वजह से डिलीवरी के बाद इनमें तेज दर्द उठ सकता है।

गर्भावस्था में और डिलीवरी के बाद मां और शिशु के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हार्मोंस बनते हैं। इन हार्मोनों की वजह से लिगामेंट को आराम मिलता है और मां शिशु के वजन को सहत करते हुए डिलीवरी तक पहुंच पाती है। डिलीवरी के बाद लिगामेंट को सामान्य पोजीशन में आने में समय लगता है जिससे जोड़ों में दर्द पैदा होता है।

किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से रिकवरी करना व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। आमतौर पर जोड़ों के दर्द से कुछ हफ्तों में आराम मलि जाता है लेकिन कुछ गंभीर मामलों चार से छह महीनों तक दर्द रह सकता है।

अगर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कोई समस्या नहीं हुई हो और डिलीवरी ठीक रही हो तो दर्द से उबरने की संभावना ज्यादा होती है। डिलीवरी के बाद अच्छी देखभाल और पिछली किसी चोट और स्वास्थ्य समस्या का पता लगाकर आप जान सकती हैं कि दर्द से कब तक छुटकारा मिलेगा।

रोज हल्की एक्सरसाइज करें। आपको बस ऐसी एक्सरसाइज करनी हैं जिनकी मदद से शरीर एक्टिव रहे। इससे जोड़ों में दर्द कम होता है। एक्सरसाइज से जोड़ों पर दबाव नहीं पड़ता। दर्द को कम करने के लिए गर्म या ठंडी सिकाई भी कर सकती हैं। बर्फ की सिकाई से भी दर्द कम होता है। प्रभावित हिस्से बर्फ या गर्म बैग सीधा न लगाएं बल्कि तौलिए में आईस बैग को लपेटकर लगाएं। शरीर की मालिश करने से अच्छा और कोई उपाय नहीं है। जोड़ों की मालिश करवाएं। आप किसी तेल या ऑइंटमेंट से भी मालिश कर सकती हैं। जोड़ों में दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ महिलाओं को एक्यूपंक्चर से भी आराम मिल सकता है। आप घर पर भी एक्यूपंक्चर कर सकती हैं। एक्यूपंक्चर की तकनीक से शरीर की विशेष बिंदुओं को दबाया जाता है जिससे दर्द में कमी आती है।

शरीर में होने वाली खुजली को कम कर देगा घरेलू नुस्खा

आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की त्वचा बहुत रूखी होती है। रूखी त्वचा होने के कारण उनको शरीर में अक्सर खुजली की समस्या बनी रहती है। इसके साथ-साथ दूषित पानी या फिर दवाइयों का सेवन करने के कारण भी शरीर में खुजली की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान ना देना भी शरीर में होने वाली खुजली का प्रमुख कारण माना जाता है। इस समस्या से बचने के लिए यहां पर एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताया जा रहा है जिसे आप घर बैठे आजमा सकते हैं।

इसका ना तो कोई साइड इफेक्ट है और ना ही इससे आपके शरीर को किसी खास एलर्जी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप अपने शरीर में होने वाली खुजली से राहत पाना चाहते हैं तो यहां बताए जा रहे घरेलू नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं। जिन लोगों को शरीर में खुजली की समस्या है उन्हें सबसे पहले अपने नहाने के पानी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी दूषित पानी भी खुजली का प्रमुख कारण होता है। इस घरेलू नुस्खे को आजमाने से पहले आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप जिस पानी से नहा रहे हैं वह पानी साफ-सुथरा है और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं आ रही है। नहाने के पानी में आपको एक चम्मच बेकिंग सोडा और 2-3 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। यह सामग्री आपको अपने घर में ही मिल जाएगी।

इसे पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसके बाद इसी पानी से नहाएं। हफ्ते में 4 से 5 दिन तक इसी तरह पानी में बेकिंग सोडा और नींबू रस को मिलाएं और इसी पानी से नहाएं। आपको हफ्ते भर में फायदा दिखने लगेगा।

खुजली की समस्या को दूर करने के लिए इन दोनों सामग्रियों में विशेष गुण पाया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार, नींबू और बेकिंग सोडा दोनों स्किन सूदिंग का गुण रखते हैं। इसके साथ-साथ यह स्किन इरिटेशन और इचिंग को कम करने की विशेष क्रिया को बढ़ाने में मदद करते हैं।

इसलिए खुजली से परेशान लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल इस समस्या को दूर करने में काफी राहत दिला सकता है। आपको बता दें कि यह घरेलू नुस्खा खुजली की समस्या को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य मेडिकल कंडीशन होने पर आपको बिना देर किए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

2027 की राह में कांग्रेस की 'अग्निपरीक्षा'

◆सत्ता विरोधी माहौल की उम्मीद, लेकिन संगठनात्मक मजबूती
◆एकजुटता और जमीनी सक्रियता ही तय करेगी कांग्रेस की दिशा
◆भाजपा के बूथ अभियान के बीच कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति धीरे-धीरे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। भाजपा जहां संगठन विस्तार, लाभार्थी संपर्क अभियान और विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा का मुकाबला करने से पहले अपने संगठन को पूरी तरह सक्रिय और एकजुट बनाए रखने की है। किसी भी चुनाव में केवल सरकार के खिलाफ माहौल पर्याप्त नहीं होता। विपक्ष को जनता के सामने विश्वसनीय विकल्प भी प्रस्तुत करना पड़ता है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने यही सबसे बड़ी परीक्षा है।

प्रदेश कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में जिला और ब्लाक स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की कोशिशें तेज की हैं। विभिन्न मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास को लेकर पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन मुद्दों को चुनावी लाभ में बदलने के लिए बूथ स्तर तक मजबूत संगठन और लगातार जनसंपर्क आवश्यक होगा। उत्तराखंड जैसे राज्य में स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रियता चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। उत्तराखंड कांग्रेस के सामने समय-समय पर नेतृत्व और समन्वय की चुनौतियां भी चर्चा में रही हैं। चुनाव नजदीक आते ही कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और टिकट की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। यदि पार्टी नेतृत्व सभी वरिष्ठ नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने में सफल रहता है, तो संगठन को मजबूती मिल सकती है। लेकिन यदि आंतरिक मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं, तो उसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है।

कांग्रेस की राजनीति फिलहाल जनसरोकारों के मुद्दों पर केंद्रित दिखाई दे रही है। इनमें प्रमुख रूप सेकृ बेरोजगारी और रोजगार के अवसर, पलायन और खाली होते गांव, शिक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, महंगाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सड़क, पेयजल और बुनियादी सुविधाएं, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास हैं। पार्टी इन मुद्दों के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह मुद्दे मतदाताओं तक किस प्रभावी तरीके से पहुंचते हैं। दूसरी ओर भाजपा लगातार बूथ प्रबंधन, लाभार्थी संपर्क और सामाजिक वर्गों के बीच संगठन विस्तार पर जोर दे रही है। महिला, युवा, किसान और अनुसूचित वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के लिए अलग-अलग मोर्चे सक्रिय किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने केवल सरकार की आलोचना करने से आगे बढ़कर वैकल्पिक दृष्टि और स्पष्ट विकास एजेंडा प्रस्तुत करने की चुनौती है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और महिला मतदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। रोजगार, शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे इन वर्गों के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कांग्रेस इन वर्गों के बीच प्रभावी संवाद स्थापित कर पाती है, तो उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है। वहीं भाजपा भी इन्हीं वर्गों पर विशेष फोकस बनाए हुए है। उत्तराखंड में पलायन आज भी सबसे गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में शामिल है। खाली होते गांव, खेती का संकट और सीमांत क्षेत्रों में घटती आबादी लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को राजनीतिक बहस का केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मतदाता केवल समस्या नहीं, बल्कि उसके व्यावहारिक समाधान भी सुनना चाहेंगे।

राजनीतिक दृष्टि से अभी चुनाव में समय है और आने वाले महीनों में परिस्थितियां बदल सकती हैं। संगठनात्मक बदलाव, स्थानीय समीकरण, राष्ट्रीय राजनीति, सरकार के फैसले और जनभावनाएं चुनावी तस्वीर को प्रभावित करेंगी। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने संगठन को पूरी तरह सक्रिय कर भाजपा के मुकाबले मजबूत विकल्प के रूप में उभर पाएगी, या फिर आंतरिक चुनौतियां उसकी चुनावी तैयारी को प्रभावित करेंगी। उत्तराखंड की राजनीति अब तैयारी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा सत्ता बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस वापसी का अवसर तलाश रही है। लेकिन चुनावी सफलता केवल नारों या आरोप-प्रत्यारोप से तय नहीं होगी। जनता उस दल पर भरोसा करेगी जो मजबूत संगठन, स्पष्ट नेतृत्व, विश्वसनीय नीतियां और स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेगा। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस अवसर को जनसमर्थन में बदल पाती है या नहीं।

शब्द सामर्थ्य -005

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. तकलीफ, कष्ट, कठिनाई, परेशानी 3. सरल, सहज 6. ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा लेना 7. विवश, लाचार 8. अत्यधिक ठंडा, सुस्त 9. अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत 11. सूर्य, सूरज 13. वस्त्र आदि धारण कराना 15. अप्रसन्न, नाखुश 16. खिंचाव, आकर्षण शक्ति (उ.) 18. एक रंग, आसमानी रंग 22. सेवा-सत्कार, आवभगत 23. सर्प, सांप, लकड़ी आदि की मूर्ति बनाना।

ऊपर से नीचे

1. हृदर, उर 2. शिष्टता, भद्रता, विवेक (उ.) 3. अंततः, अंततोगत्वा 4. अच्छी शिक्षा, नेक सलाह 5. आवागमन, गमनागमन 7. पुरुष 8. घोड़े की तेज चाल, तेज गति की दौड़ 10. लूटपाट, डकैती 12. बबार्दी, तबाही 14. नासिका, श्वसनइंद्रीय 17. आखेटक, अरेही 19. योग्य, काबिल 20. कामदेव की पत्नी, प्रेम, आनंद 21. रात्रि, निशा।

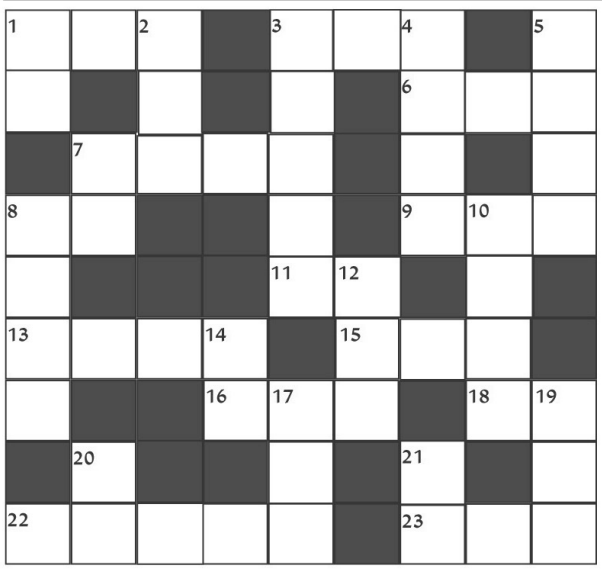

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 04 का हल

चु	स्त		मु		सं	स्था	न	
ग		म	र्दा	न	गी		त	म
ली	प	ना			त	न		
	ना	ना					ज	
मा	ह		रा		सा	ज	न	
न		स	ह	दे	व		म	द
व		म		व	न	ज		ल
ता	क	त	व	र		मी		द
	ल	ल	क		क	र	त	ल

बारिश में भीग भी जाएं तो भी खराब नहीं होगा मेकअप!

मानसून का मौसम आते ही महिलाओं को सबसे बड़ी चिंता होती है मेकअप की. खासकर अगर आप कॉलेड गोइंग है, वर्किंग वुमेन हैं या फिर किसी खास पार्टी फंक्शन के लिए तैयार होने वाली हैं तो मेकअप करने से पहले आपका बारिश के मिजाज़ को समझना पड़ता है. लेकिन अब हम आपको ऐसे स्मार्ट मेकअप टिप्स देने जा रहे हैं जो बारिश में भीग जाने पर भी खराब नहीं होगा. यानि आप अगर बारिश में नहा भी लें तो भी ये मेकअप फैलेगा नहीं. तो आइए जानते हैं मानसून में मेकअप करने के ये स्मार्ट टिप्स जो आपको और भी सुंदर बना देंगे

– मानसून के मौसम में मेकअप करने से पहले अपने चेहरे पर मैटिफाइंग प्राइमर लगाएं ऐसा करेंगी तो आपका मेकअप बारिश के दिनों में ज्यादा देर तक स्टे करेगा.

– फाउंडेशन लगाने से बचना नहीं है. कुछ लोग बारिशों में फाउंडेशन ना लगाने की सलाह भी देते हैं लेकिन आपको वॉटर प्रूफ या फिर जेल मिक्स करते फाउंडेशन को लाइट बनाकर फिर उसे स्किन पर अप्लाई करना चाहिए. ऐसा करने से आपका फाउंडेशन दिनभर चेहरे पर स्टे करेगा और बारिश की बूंदो से खराब भी नहीं होगा.

– बारिशों के दिनों में सिर्फ वॉटरप्रूफ आईलाइनर की ही इस्तेमाल करें. तेज बारिश में भी ये आपकी आंखों की खूबसूरती खराब नहीं होने देगा

– आईशैडो लगाना अगर आपको पसंद हैं तो मानसून में वाइब्रेंट कलर का चुनाव करें बस एक बात का ख्याल रखें की आईशैडो भी वॉटरप्रूफ ही होना चाहिए

– मस्कारा अगर वॉटर प्रूफ लगा रही हैं तो टेंशन की बात नहीं है लेकिन वॉटर प्रूफ मस्कारा नहीं है तो आप इसे मेकअप करते समय अवॉयड भी कर सकती हैं.

– लिपस्टिक के बिना मेकअप अधूरा है. लेकिन बारिश में लिपस्टिक फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है ऐसे में आपको सिर्फ मैट लिपस्टिक ही लगानी चाहिए. ग्लोसी या क्रीम लिपस्टिक गलती से भी ना लगाएं.

– अपने पास हमेशा ब्लोटिंग पेपर रखें. अगर बारिश की बूंदे आपके चेहरे पर पड़ी हैं तो आप किसी तौलिये या कपड़े से उसे ना पौंछे इससे मेकअप खराब हो जाता है. मेकअप पर ऊपर से पानी पड़ जाए या स्किन का एक्सेस ऑयल निकले उसे हमेशा ब्लोटिंग पेपर से ही साफ करना चाहिए

– सारा दिन मेकअप को फ्रेश लुक देने के लिए सबसे लास्ट में सेटिंग स्प्रे जरूर अप्लाई करें. इससे आपका मेकअप बारिश की बूंदों से फैलेगा नहीं. एक तरीक से ये सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप की कोटिंग कर देता है.

तो बारिश के मौसम में अगर इन बातों का ख्याल रखेंगी को आपकी स्किन का ग्लो हमेशा बना रहेगा. जो लड़कियां या महिलाएं बारिश में मेकअप करने से डरती हैं उन्हें इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए. अगर आप मानसून में मेकअप करते समय इन बातों का ख्याल रखेंगी तो आपका मेकअप कभी खराब नहीं होगा.

तेजी से पॉपुलर हो रहा है एक्सरसाइज स्नैकिंग

क्या आप भी समय न होने का बहाना बनाकर एक्सरसाइज से बचते हैं या फिर सचमुच आपकी दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि आपको वर्कआउट करने का टाइम ही नहीं मिलता तो अब आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आ गया है। आजकल परफेक्टस एक्सराइज का एक नया ऑप्शन ट्रेंड में चल रहा है। यह उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, जो समय की कमी से अपने फिटनेस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसका नाम एक्सरसाइज स्नैकिंग है। आइए जानते हैं एक्सरसाइज के इस नए तरीके के बारें में।

अगर आप एक्सराइज करने के लिए दिन में एक निश्चित समय तय नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सरसाइज स्नैकिंग आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे दिन में एक साथ ज्यादा खाना न खा पाने वाले थोड़ा-थोड़ा कुछ न कुछ खाते रहते हैं। यह एक तरह का मिनी वर्कआउट भी कहा जा सकता है। जिसे दिन में कई बार कुछ मिनट्स के लिए कर सकते हैं। 5-10 मिनट की एक्सरसाइज स्नैकिंग भी बेहद फायदेमंद हो सकती है।

आजकल लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि वर्कआउट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में दिन में कई बार छोट-छोटे वर्कआउट्स कर खुद को फिट रख सकते हैं। इसके लिए किसी एक समय की जरूरत भी नहीं होती है। यह इतना सिंपल तरीका है कि इसे आप घर, ऑफिस या कहीं भी छोटी सी जगह में भी कर सकते हैं। इसमें न तो आपको पसीना बहाना है और ना ही ज्यादा मेहनत करनी है। एक्सरसाइज स्नैकिंग वर्कआउट का इतना अच्छा ऑप्शन है कि दिल और पेट की सेहत को दुरुस्त रखने का काम करता है। इससे डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार 10 मिनट की एक्सरसाइज स्नैकिंग भी 30 मिनट के वर्कआउट से बेहतर हो सकती है। हालांकि, ध्यान रखें कि इसे करने से पहले स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लें।

एक्सरसाइज स्नैकिंग में क्या-क्या कर सकते हैं

1. सीढ़ी चढना़-उतरना 2. थोड़े-थोड़े समय पर तेजी से चलना

3. काम के बीच 5-5 मिनट तक चलना

सुना जाना सबसे जरूरी होता है:सना सईद

सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान की बेटी अंजलि का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री सना सईद ने सोशल मीडिया पर अपना एक अनुभव साझा किया। दरअसल, उन्होंने विदेश में रहने के दौरान भाषा, उच्चारण और संवाद से जुड़ी कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात की। सना सईद आज लॉस एंजिल्स में रहती हैं और अपने करियर और जीवन को नए तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने अमेरिका पहुंचने के शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प अनुभव बताया। सना ने बताया, साल 2016 में मैं पहली बार पढ़ाई के लिए लॉस एंजिल्स आईं थी। इस दौरान मुझे रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे याद है कि एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी और वहां पानी पीना चाहती थी लेकिन मेरा उच्चारण वहां के लोगों को ठीक से समझ नहीं आया। मैंने कई बार वॉटर कहा, लेकिन रेस्टोरेंट वाला अलग-अलग चीज समझता रहा और यहां तक कि सोडा या कोक तक ऑफर करने लगा।

उन्होंने आगे कहा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे अमेरिका में लंबे समय तक रहना है, तो मुझे अपने बातचीत करने के तरीके पर काम करना होगा, क्योंकि सुना जाना सबसे जरूरी है। इसके बाद मैंने अपने उच्चारण और बोलने के तरीके पर ध्यान देना शुरू किया और इसके लिए ट्रेनिंग भी ली।

सना ने बताया कि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। किसी नए देश में जाकर वहां की भाषा के अनुसार खुद को ढालना बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा होता है। उन्होंने कहा, कई लोग सोचते हैं कि उच्चारण बदलना बहुत आसान है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत मेहनत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, मुझे इस बात से परेशानी होती है कि लोग अक्सर किसी के उच्चारण का मजाक उड़ाते हैं या उसे गलत समझते हैं। हर व्यक्ति का बोलने का अपना तरीका होता है, जो उसकी संस्कृति और पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है। इसलिए किसी के उच्चारण को लेकर नकारात्मक टिप्पणी करना सही नहीं है।

आवारापन 2- इमरान हाशमी की गैंगस्टर शिवम के रूप में हुई वापसी

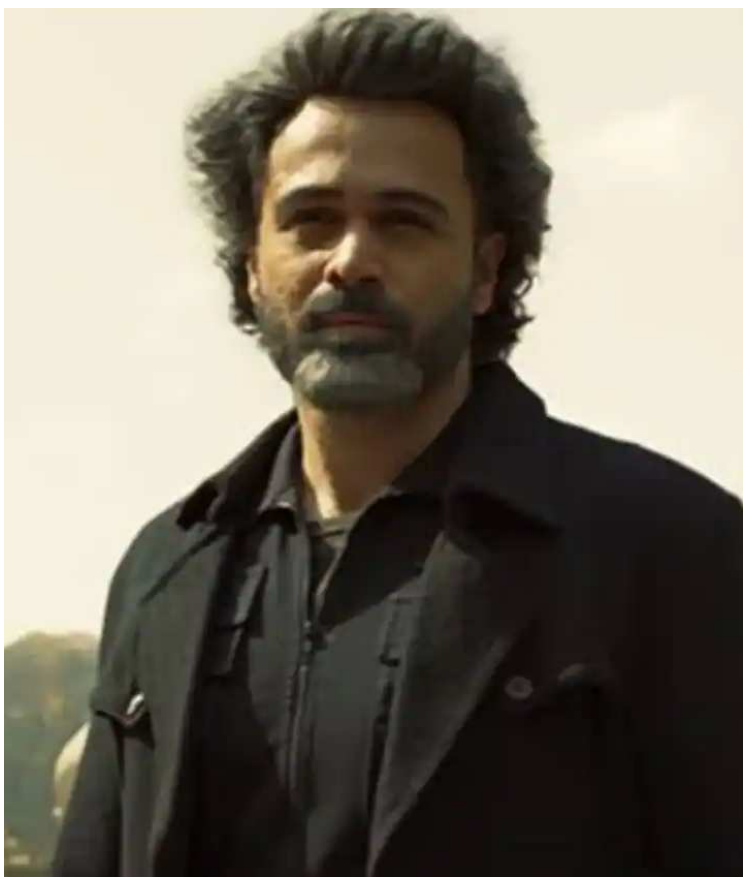

सीरियल किसर इमरान हाशमी स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2 में अभिनेता इमरान हाशमी अपने 19 साल पुराने उलझे हुए किरदार शिवम पंडित के रूप में वापसी कर रहे हैं. टीजर फैंस को सीक्वल में गैंगस्टर दुनिया की एक झलक दिखाता है, जो काफी जोखिम भरी और रोमांचक है. एक्स हैंडल पर आवारापन 2 के टीजर की जमकर तारीफ हो रही है और लोगों को 19 साल पुराना शिव पंडित का दौर याद आ गया है.

फिल्म में दिशा पटानी और दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी को दमदार खलनायिका नफीसा के रूप में दिखाया गया है, जो आंखों में कई रहस्य लिए नजर आती हैं. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी फिल्म के टीजर में एक्शन और इमोशनल सीन दिख रहे हैं. सीक्वल के टीजर ने साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म के भावनात्मक मोड़ को पकड़े रखा है.

बता दें, इस कल्ट हिट फिल्म की रिलीज के 19 साल पूरे होने के मौके पर जारी किए गए टीजर ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. टीजर की शुरुआत इमरान के किरदार शिवम के अपने अतीत की दर्दनाक यादों को याद करने से होती है. इसके बाद हमें एक दमदार स्ट्रीट फाइटर के रूप में उनकी हाथापाई और गैंगस्टरों से लड़ते हुए झलकियां देखने को मिलती हैं, जबकि शबाना का इंटेंस लुक नजर आता है. दिशा का रहस्यमयी किरदार वायलिन बजाते हुए दिखाया गया है. टीजर इमरान हाशमी के इस डायलॉग के साथ खत्म होता है, इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.

इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. इमरान हाशमी इस बार शिवम पंडित के रोल में और भी ज्यादा जान डालते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने टीजर में इमरान हाशमी के एंट्री सीन पर लिखा है, अब तक सबसे धांसू एंट्री सीन. दूसरे यूजर ने टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार बताया है. एक और लिखता है, टीजर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. सोशल मीडिया पर आवारापन 2 के टीजर की तारीफ की झड़ी लग चुकी है.

फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है. विशेष भट्ट की फिल्म एक दिल को छू लेने वाले संगीत के साथ लौट रही है, जिसमें मिथुन और सईद कादरी ने फैंस के पसंदीदा गानों तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता को नए अंदाज में पेश किया है. साथ ही कुछ नए गाने भी शामिल किए हैं. फिल्म की शूटिंग बैंकॉक के साथ-साथ भारत के कई हिस्सों में हुई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है. फिल्म 14 अगस्त, 2026 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

कांवड़ यात्रा -2026: ढालवाला में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

संवाददाता

टिहरी। कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चौकी ढालवाला क्षेत्र में पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

आज यहां एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देशन में पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने चलाया विशेष अभियान, व्यापारियों को रेट लिस्ट प्रदर्शित करने एवं निर्धारित दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के दिए निर्देश कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चौकी ढालवाला क्षेत्र में टिहरी पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अस्थायी एवं अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे मार्ग को बाधारहित बनाते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु किया जा सके। संयुक्त टीम ने संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी। इस अवसर पर ढाबा, होटल एवं भोजनालय संचालकों को अपनी प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने, निर्धारित दरों पर ही सामग्री उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रतिष्ठानों के बाहर अनावश्यक सामान रखकर मार्ग अवरुद्ध न करने एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया गया।

पुलिस एवं प्रशासन की ओर से सभी व्यापारियों से अपील की गई कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें तथा प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यात्रा को सकुशल एवं व्यवस्थित संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें। टिहरी पुलिस की अपील: कांवड़ यात्रा सेवा, सुरक्षा एवं सहयोग का पर्व है। सभी नागरिक, व्यापारी एवं श्रद्धालु प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित, स्वच्छ एवं व्यवस्थित कांवड़ यात्रा में अपना सहयोग दें।

सू- दोकू क्र.005

	8				1		5	
6			8			2		3
	3				2		1	
		3		9		5		4
5			3				9	
		4		2				6
4			2		3		6	
		6				8		7
	2	9	7		6			

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र 04 का हल

5	3	9	7	4	8	6	2	1
2	1	6	5	9	3	4	7	6
4	7	8	1	6	2	3	5	9
3	6	1	8	5	9	2	4	7
8	5	2	3	7	4	1	9	6
7	9	4	2	1	6	8	3	5
6	4	7	9	2	1	5	6	3
1	8	5	4	3	7	9	6	2
9	2	3	6	8	5	7	1	4

'कांवड़ यात्रा' आस्था की सबसे बड़ा 'कारवा'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तराखंड की धरती पर एक अलग ही उत्साह दिखाई देने लगता है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गूंजता हर-हर महादेव का जयघोष, गंगा तट पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़, कंधों पर सजी रंग-बिरंगी कांवड़ और हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा का संकल्प यह दृश्य केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का भी परिचायक है। कांवड़ यात्रा आज दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश और अन्य पवित्र स्थलों से गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों में जलाभिषेक करने निकलते हैं। लेकिन इस यात्रा का महत्व केवल भगवान शिव की पूजा तक सीमित नहीं है। यह यात्रा भारत की विविधता, सामाजिक समरसता, सेवा-भाव और लोकजीवन की ऐसी झांकी प्रस्तुत करती है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। विष की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र नदियों का जल भगवान शिव को अर्पित किया। इसी प्रसंग को कांवड़ यात्रा की मूल प्रेरणा माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार, त्रेता युग में भगवान परशुराम ने गंगाजल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कई परंपराओं में यह भी माना जाता है कि रावण ने भी कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव की आराधना की थी। समय के साथ यह धार्मिक परंपरा जनआस्था के विराट उत्सव में बदल गई। यदि कांवड़ यात्रा की आत्मा कहीं बसती है तो वह उत्तराखंड है। देवभूमि की गोद में बहने वाली मां गंगा का पवित्र जल ही इस यात्रा का केंद्र है। हरिद्वार की हर की पैड़ी, ऋषिकेश के घाट और गंगोत्री धाम से लाखों श्रद्धालु जल भरकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों की ओर निकल पड़ते हैं। सावन के दिनों में हरिद्वार केवल एक धार्मिक नगर नहीं रहता, बल्कि पूरे भारत का सांस्कृतिक संगम बन जाता है। यहां अलग-अलग भाषाएं सुनाई देती हैं, विभिन्न राज्यों की वेशभूषाएं दिखाई देती हैं और हर कदम पर भारत की विविधता का अनुभव होता है।

◆गंगाजल से भरी कांवड़ केवल जल का पात्र नहीं, बल्कि यह है भारत की सांस्कृतिक एकता
◆लोकपरंपराओं, सेवा-भाव और देशभर के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है कांवड़ यात्रा
◆हरिद्वार से निकलने वाली यह यात्रा बन चुकी है देश को जोड़ने वाली जीवंत सांस्कृतिक धारा

कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सांस्कृतिक विविधता है। राजस्थान के केसरिया साफे, पंजाब के ढोल, हरियाणा के अखाड़े, उत्तर प्रदेश की भजन मंडलियां, उत्तराखंड के ढोल-दमाऊं, बिहार की लोकधुनें और मध्य प्रदेश के पारंपरिक भजन सब एक ही यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। कई स्थानों पर कलाकार लोकनृत्य प्रस्तुत करते हैं। कहीं शिव तांडव की झांकी निकलती है तो कहीं भगवान शिव और माता पार्वती की झलकियां श्रद्धालुओं का स्वागत करती हैं। उत्तराखंड के लोकवाद्य ढोल-दमाऊं, रणसिंघा और पारंपरिक भजन यात्रा को स्थानीय सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं। यह दृश्य सचमुच एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करता है।

कांवड़ यात्रा का सबसे प्रेरक पक्ष सेवा की परंपरा है। यात्रा मार्ग पर हजारों सेवा शिविर लगाए जाते हैं। इनमें श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, पानी, दवाइयां, प्राथमिक उपचार, विश्राम, मोबाइल चार्जिंग, दूध, फल और कई स्थानों पर रात्रि विश्राम तक की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इन शिविरों को धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, स्थानीय व्यापारी, स्वयंसेवी समूह और ग्रामीण मिलकर संचालित करते हैं। कई परिवार वर्षों से अपने निजी संसाधनों से सेवा शिविर लगाते आ रहे हैं। उनके लिए यह दान नहीं, बल्कि भगवान शिव की सेवा का माध्यम है। यही सेवा-भाव भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को जीवित रखता है जिसमें अतिथि, साधु और यात्री की सेवा को पुण्य माना गया है।

कांवड़ यात्रा का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है, जिस पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है। सावन के दौरान उत्तराखंड के हजारों छोटे व्यापारियों, होटल संचालकों, ढाबों, फल विक्रेताओं, फूल-माला विक्रेताओं, हस्तशिल्प कारोबारियों, परिवहन सेवाओं और स्थानीय दुकानदारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। रंग-बिरंगी कांवड़, भगवा वस्त्र, पूजा सामग्री, धार्मिक झंडे, ढोल, शिव प्रतिमाएं, प्रसाद और स्मृति चिह्नों का कारोबार कई गुना बढ़ जाता है। अस्थायी रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। स्थानीय युवाओं को परिवहन, लाजिस्टिक्स, खानपान और अन्य सेवाओं में काम मिलता है।

केंद्रीय विद्यालय बीएचईएल हरिद्वार में आयोजित कला महोत्सव में 8 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

संवाददाता

हरिद्वार। केंद्रीय विद्यालय बीएचईएल, हरिद्वार में पिछले दिनों राट्रीय एकता पर्व-2026 के अंतर्गत दो दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। भारत की विविध सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कला विधाओं पर आधारित इस आयोजन में आठ केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने 16 विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेजबानी केंद्रीय विद्यालय बीएचईएल, हरिद्वार द्वारा की जा रही है।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पार्थ सारथी गौड़ा, चेयरमैन नॉमिनी, वीएमसी एवं एजीएम (एचआर), बीएचईएल हरिद्वार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य बृजेश पाल सिंह भी उपस्थित रहे। निर्णायकों का परिचय एवं प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा के साथ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ।

विद्यालय के सभागार में विद्यार्थियों ने एक भारत श्रेठ भारत श्रेणी के अंतर्गत समूह राट्रीय गीत एवं समूह राट्रीय नृत्य की आर्काक प्रस्तुतियां दीं। वहीं कला उत्सव श्रेणी में एकल एवं समूह गायन तथा एकल एवं समूह नृत्य प्रतियोगिताओं

में प्रतिभागियों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही द्वि-आयामी (2-डी), त्रि-आयामी (3-डी) एवं स्वदेशी कला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने उत्तराखंड के युग्म राज्य तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए पारंपरिक खिलौनों और स्थानीय खेलों का आर्काक प्रदर्शन किया।

मुख्य अतिथि पार्थ सारथी गौड़ा ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभागियों की रचनात्मकता और प्रस्तुति ने उन्हें अभिभूत कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में कला, संस्कृति और राट्रीय एकता की भावना को सशक्त बनाते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित निर्णायक एवं दर्शकों ने भी प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

विद्यालय के प्राचार्य बृजेश पाल सिंह ने अपने संबोधन में भारत की सांस्कृतिक विविधता को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि यही विविधता राट्र की प्रगति और एकता का आधार है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि एवं निर्णायकों का पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। मेजबान विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत तथा गुजराती लोकनृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को रंगारंग शुरुआत दी।

चम्पावत आन्तरिक मार्गों के लिए 1.87 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त जारी

हमारे संवाददाता

चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में चौमुखी विकास की गति को तेज करने तथा आम जनमानस को बेहतर अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन द्वारा जनपद चम्पावत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मैरोली एवं ग्राम पंचायत बडपास में आन्तरिक मार्गों के इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा नव-निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना हेतु कुल 3.89 करोड़ रूपये की लागत के सापेक्ष प्रथम किस्त के तौर पर 1.87 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से दोनों ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की मुख्यधारा को पहुँचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत मैरोली एवं बडपास में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य बिना किसी विलंब के शुरू किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और मानकों से किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फरार चल रहा गैंगस्टर गिरफ्तार, गोकशी मामले में था वांछित

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। गोकशी मामले में फरार चल रहे एक गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार बीती 24 जुलाई को कोतवाली रूडकी पुलिस ने एक सूचना के आधार पर ग्राम जोरासी मटर फैक्ट्री के पीछे छापेमारी की गई तो गोकशी कर रहा आरोपी नौमान उर्फ काला मौके से फरार हो गया। टीम ने मौके से 100 किलो ग्राम गोमांस बरामद किया जिस आधार पर कोतवाली रुड़की पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीम ने बीती रात एक सूचना के आधार पर आरोपी नौमान उर्फ काला को लक्सर रोड लंढौरा चौक से गिरफ्तार किया गया जिसके एक अन्य साथी की तलाश भी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है।

सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन का धरना 11वें दिन भी जारी

संवाददाता

देहरादून। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के तत्वाधान देहरादून नगर निगम में 11 वे दिन भी धरना रहा जारी और देहरादून शहर में सभी जगह कार्य बहिष्कार रहा पर्यावरण मित्रों द्वारा क्षेत्र में काम नहीं किया गया लेकिन अपने हाजिर स्थल पर उपस्थित रहे इसी उपरांत सचिवालय में मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया वार्ता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष / संरक्षक चौधरी नरेश वैध के नेतृत्व में हुई इस दौरान विनय शंकर पांडे को 7 सूत्र मांग पत्र सोपा गया जिसमें 6 मांगों पर विचार विमर्श किया गया। सचिव शहरी विकास रितेश झा के अवकाश पर रहने के कारण पुनः वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। वार्ता में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे, उपनगर आयुक्त तनवीर, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आनंद शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त राजवीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूरी यूनियन के नगर निगम शाखा अध्यक्ष सुनील कुमार सोनू खैरवाल, यूनियन के सचिव धीरज भारती, सत्येंद्र कुमार, योगेश आनंद, वाहन चालक संघ के नगर निगम अध्यक्ष स्वर्ण सिंह पवार, वार्ता में शामिल रहे। धरने पर बैठने वालों में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन की देहरादून महानगर अध्यक्ष कु. आरती यूनियन के उपाध्यक्ष विनोद कुमार, अरविंद कुमार, पप्पू, तेजपाल आदि सैकड़ो कर्मचारी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया 'ट्रेंड' और चुनावी 'दावे'.. ◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

और स्वास्थ्य के माडल की बात कर सकती है। बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं।

उत्तराखंड की राजनीति फिलहाल दावों और संभावनाओं के दौर में है, निष्कर्षों के नहीं। भाजपा अपनी उपलब्धियों के भरोसे चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस जनता के मुद्दों को हथियार बनाएगी। क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि चुनावी नतीजे अभी किसी के पक्ष में तय नहीं हैं। राजनीतिक बयान, सोशल मीडिया ट्रेंड और चुनावी दावे अपनी जगह हैं, पर अंतिम फैसला उत्तराखंड की जनता मतदान वाले दिन करेगी। पहाड़ का मतदाता कई बार ऐसे फैसले देता है जो चुनाव पूर्व सभी राजनीतिक आकलनों को गलत साबित कर देते हैं। इसलिए 2027 की लड़ाई अभी खुली है और हर दल के सामने अवसर भी है, चुनौती भी।

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन-1905 पर जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए सख्त निर्देश

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा जवाबदेही हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग एवं जल जीवन मिशन से संबंधित अधिक संख्या में प्राप्त शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय पर जन शिकायतों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन शिकायतों का निर्धारित समयावधि में समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी स्तर पर की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन तथा अन्य श्रेणियों में परिवर्तित की गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर दोनों मंडलायुक्त तथा शासन स्तर पर सभी सचिव समाधान दिवस के माध्यम से जन समस्याओं की नियमित सुनवाई एवं समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस को प्रभावी जनसेवा के मंच के रूप में विकसित किया जाए तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि वे अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के दृष्टिगत नवाचार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी नवाचारों की विस्तृत सूची 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रथम माह से ही पेंशन प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने के निर्देश दिए।

प्रशिक्षित बेरोजगारों का धरना 57वें दिन भी जारी

संवाददाता

देहरादून। शारीरिक (व्यायाम) प्रशिक्षित बेरोजगारों का शिक्षा निदेशालय में धरना 57वें दिन भी जारी रहा।

संवाददाता

देहरादून।आज यहां उत्तराखंड के शारीरिक (व्यायाम) प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षा निदेशालय में 4 जून से शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे। आज धरने का 57वे दिन होने के पश्चात भी सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षकों की कोई सुध नहीं ली गई इसलिए 19 जून से शारीरिक प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षा निदेशालय में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है 42 वे दिन संजय कोरंगा, भुवनेश बिष्ट, संजय कोरंगा, महेश सिंह बैठे हैं। अभी तक सरकार शासन प्रशासन किसी ने व्यायाम प्रशिक्षित बेरोजगारों की सुध नहीं ली अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो अब हम आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षको की मांग है कि नई शिक्षा नीति के तहत शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटरमीडिएट विद्यालय तक अनिवार्य रूप से की जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक (व्यायाम)शिक्षक) फाईल सख्या 77006 को वित्त विभाग से मन्जूरी दिलाकर कैबिनेट में पास किया जाये। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी जाए। आज शिक्षा निदेशालय में धरने में निम्न प्रशिक्षित महेश नेगी, संजय कोरंगा, भुवनेश बिष्ट आदि लोग अनिश्चितकालीन धरने पर शिक्षा निदेशालय में बैठे।

उक्रांद ने सीता माता मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठायी

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड क्रांति दल ने बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के कार्यालय पहुंचकर सीता माता मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठायी।

आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन सिंह सजवाण के नेतृत्व में बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के ऋषिकेश स्थित कार्यालय में मुख्य कार्याधिकारी से जनपद चमोली के चांई-ज्योतिर्मठ में उत्तर भारत के एकमात्र पौराणिक सीता माता मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर भेंट वार्ता की गई। मुख्य कार्याधिकारी ने अतिशीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन सिंह सजवाण ने कहा कि ज्योतिर्मठ के चांई गाँव में माता सीता का पौराणिक मन्दिर बहुत ही दयनीय स्थिति में है और माता सीता की शिला को अन्यत्र एक कमरे में रखकर पूजा की जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी द्वारा पूर्व में मन्दिर निर्माण हेतु टेण्डर भी जारी किया गया था परन्तु विभागीय मनमानी के कारण उसे बाद में निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय जनता का कहना है कि बीकेटीसी के अध्यक्ष ने मंदिर निर्माण में अपनी मनमानी करने का प्रयास किया जबकि स्थानीय जनता मंदिर को भव्य व स्थानीय संस्कृति के अनुसार बनाना चाह रही थी। उन्होंने अध्यक्ष को चेतावनी दी कि अगर अतिशीघ्र जनभावना के अनुरूप मंदिर का निर्माण न किया गया तो उनका घेराव किया जाएगा। केंद्रीय उपाध्यक्ष मोहन सिंह असवाल जी ने कहा कि यदि बीकेटीसी द्वारा अतिशीघ्र मंदिर निर्माण न करवाया गया तो उक्रांद उग्र आंदोलन करेगा। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष प्रवीण रमोला, चमोली जिला उपाध्यक्ष अनिल राणा, रमेश रतूड़ी आदि उपस्थित थे।

'ऐतिहासिक' दावे पर युवाओं की 'शंका'!

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। लोकसभा में एंटी पेपर लीक कानून संशोधन विधेयक पारित होते ही भाजपा ने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक और निर्णायक कदम बताया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि अब परीक्षा माफिया की कमर टूट जाएगी, नकल उद्योग पर ताला लग जाएगा और मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन संसद से लेकर सड़कों तक गूंजता एक सवाल अभी भी वहीं खड़ा है क्या केवल कानून बन जाने से युवाओं का टूटा हुआ भरोसा लौट आएगा?

राजनीति में कानून पारित होने के बाद अक्सर जश्न मनाया जाता है। इस बार भी वही हुआ। भाजपा के प्रवक्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति का हिस्सा बताया। सोशल मीडिया पर युवाओं की जीत और पेपर माफिया की हार जैसे संदेश चलने लगे। लेकिन इन नारों के बीच देश का वह अभ्यर्थी कहीं दिखाई नहीं दिया, जिसने पिछले पांच वर्षों में दो-दो, तीन-तीन बार एक ही परीक्षा की तैयारी की और हर बार पेपर लीक की खबर सुनकर फिर से शून्य पर लौट आया।

पेपर लीक का दर्द आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। यह उस छात्र की आंखों में दिखता है, जो सुबह चार बजे उठकर पढ़ता है। यह उस पिता के माथे की लकीरों में दिखाई देता है, जिसने बेटे की कोचिंग के लिए खेत गिरवी रख दिया। यह उस बेटी की चुप्पी में सुनाई देता है, जिसने नौकरी की उम्मीद में अपनी उम्र के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष किताबों के बीच गुजार दिए। ऐसे युवाओं के लिए संसद में कानून बनना उम्मीद जरूर है, लेकिन भरोसा नहीं। भरोसा तब लौटेगा, जब परीक्षा समय पर होगी, प्रश्नपत्र सुरक्षित रहेगा और परिणाम बिना विवाद के घोषित होंगे।

यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक पक्ष भी है। भाजपा इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? यदि वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहे थे, भर्ती परीक्षाएं रद्द हो रही थीं और माफिया सक्रिय थे, तो क्या व्यवस्था पहले सो रही थी? क्या केवल कानून बना देने से उन संस्थागत कमियों पर पर्दा पड़ जाएगा, जिन्होंने इस अपराध को फलने-फूलने दिया?

◆संसद से पारित हुआ एंटी पेपर लीक बिल, पर युवाओं का सवाल
◆कानून की सख्ती से खत्म होगी साठगांठ या फिर वही पुराना खेल
◆कानून पास हुआ, भाजपा ने देशभर में बजा दी है जीत की तालियां

कानून जितना कठोर है, उतनी ही कठोर परीक्षा अब सरकार की भी होगी। क्योंकि पेपर लीक किसी बंद कमरे में नहीं होता। इसके पीछे प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परिवहन, डिजिटल सर्वर, परीक्षा केंद्र और प्रशासनिक निगरानी तक पूरी एक श्रृंखला होती है। यदि इस श्रृंखला की कमजोर कड़ियां नहीं सुधरेंगी, तो कानून की धार भी कुंद पड़ सकती है।

उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने हजारों युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। जांच हुई, गिरफ्तारियां हुईं, एसटीएफ सक्रिय हुई, लेकिन युवाओं के मन में जो अविश्वास पैदा हुआ, वह आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यही कहानी देश के कई अन्य राज्यों में भी दोहराई गई। भाजपा का यह कहना सही है कि अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो, जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से पेपर लीक होता है। यदि हर बार केवल बिचौलिये पकड़े जाएंगे और व्यवस्था के भीतर बैठे जिम्मेदार लोग बच निकलेंगे, तो कानून का संदेश अधूरा रह जाएगा।

लोकतंत्र में कानून बनाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन व्यवस्था में विश्वास पैदा करना सबसे कठिन काम है। युवाओं को संसद की कार्यवाही से अधिक अगली भर्ती परीक्षा की चिंता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस दल ने श्रेय लिया, उन्हें यह जानना है कि अगली बार उनका प्रश्नपत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं। भाजपा इस विधेयक को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में जनता के बीच ले जाएगी। विपक्ष इसकी पृष्ठभूमि और पूर्व की विफलताओं को मुद्दा बनाएगा। लेकिन चुनावी भाषणों और प्रेस कान्फ्रेंसों से अलग, देश का युवा केवल एक जवाब चाहता है क्या अब उसकी मेहनत बिकेगी नहीं? यही वह सवाल है, जिसका उत्तर किसी प्रेस विज्ञप्ति, किसी नारे या किसी सोशल मीडिया अभियान में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर मिलेगा अगली परीक्षा के दिन। जब परीक्षा समय पर होगी, पेपर लीक नहीं होगा और चयन केवल योग्यता के आधार पर होगा।

लोकसभा ने कानून पास कर दिया है। भाजपा खुश है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निर्णायक न संसद होगी, न राजनीतिक दल। निर्णायक होगा वह युवा, जो अगली भर्ती परीक्षा के बाद पहली बार कह सके इस बार मेरी मेहनत सचमुच मेरी थी।

दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। शादी का झांसा देकर लम्बे समय से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जिसे न्यायालय मे पेश कर जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार बीती 27 जुलाई को थाना कलियर में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर देकर बताया गया था कि अब्दुल रहमान पुत्र इकलाख निवासी इमलीखेडा कोतवाली पिरान कलियर जनपद हरिद्वार द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ 2020 से शादी का झांसा देकर लगतार दुष्कर्म किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म सहित पोक्सों अधिनियम की धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गयी। जिसि पुलिस ने बीती रात रहमतपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

सचिवालय के कार्मिक पर पत्नी की हत्या का आरोप!

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में तैनात एक निजी सचिव पर अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने मृतका के पति, सास व ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला डोईवाला कोतवाली क्षेत्र का है। जहां विवाह के महज आठ महीने बाद सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष के तीन लोगों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित श्रीकोट निवासी स्वर्गीय सुमेर सिंह कंडारी की बेटी सृष्टि कंडारी, जो पेशे से सरकारी शिक्षिका थीं, का विवाह नवंबर 2025 में देहरादून के डोईवाला क्षेत्रांर्तगत हर्रावाला स्थित लक्ष्मण एन्क्लेव (दिल्ली फार्म) निवासी सौरभ खत्री से हुआ था। सौरभ खत्री उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के पद पर कार्यरत है। मृतका की मां सीमा कंडारी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही सृष्टि को दहेज और अन्य बातों को लेकर लगातार मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। शिकायत में कहा गया है कि पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी और ननद चारू अक्सर उसे अपमानित करते थे और विभिन्न कारणों से परेशान करते थे।

परिजनों के अनुसार, शादी के लगभग तीन महीने बाद सृष्टि के ससुर को हार्ट अटैक आया था। बाद में उनका निधन हो गया। आरोप है कि किसी पंडित की बात का हवाला देते हुए ससुराल पक्ष ने सृष्टि को 'मनहूस' कहना शुरू कर दिया और परिवार में हो रही हर अनहोनी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इसके बाद उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और बढ़ गई। मृतका की मां सीमा कंडारी ने थाना डोईवाला में पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी और ननद चारू के खिलाफ लिखित तहरीर देकर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की संवेदनशीलता और मुख्य आरोपी के उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के पद पर कार्यरत होने को देखते हुए जांच पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) वंदना वर्मा को सौंपी गई है।

पैलेट गन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: 'पेलेट गन' पर पूरी रोक नहीं लगा सकते!

संवाददाता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह उग्र भीड़ को हटाने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर जो मानक प्रक्रिया बनाई जानी है, उसमें पेलेट गन के इस्तेमाल की स्थितियों पर भी स्पष्टता दी जाएगी। दिल्ली में संसद चलो प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से पेलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बातें कहीं हैं।

यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और दो अन्य लोगों- प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने दायर की है। प्रशांत और इरशाद ने का कहना है कि 20 जुलाई को परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स ने पेलेट गन चलाया। उसके धातु वाले छर्रे लगने से वह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां सर्जरी के जरिए उनके शरीर में घुसे छर्रों को निकाला गया।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने पेलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक की मांग को अव्यवहारिक कहा। जस्टिस बागची ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अचानक हिंसक रूप ले सकता है, ऐसे में सुरक्षा बलों को परिस्थितियों के अनुसार चरणबद्ध प्रतिक्रियादेनी पड़ती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों की नियमावली विशेष परिस्थितियों में पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देती है। याचिकाकर्ता ने उस नियम को चुनौती दिए बिना पेलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। यह याचिका अपने आप में अस्पष्ट है। इस पर वकील ने कहा कि वह सिर्फ मेटालिक पेलेट (धातु के छर्रे) के इस्तेमाल पर रोक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग प्लास्टिक या रबर पेलेट को लेकर नहीं है। जजों ने कहा वह मामले पर विचार करेंगे, लेकिन पहले याचिकाकर्ता अपनी याचिका में जरूरी संशोधन करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पेलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े नियम पेश करने के लिए कहा। साथ ही, 20 जुलाई को की गई कार्रवाई में हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े लॉग बुक (रिकॉर्ड) को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।